वार की भांति है। एक ही परिवार के लोग यहां वहां, दोनों बाजुओं में रहते हैं। परस्पर मैत्री का उनमें सम्बन्ध भी है हर माने में। ऐसी सूरत में क्या सरकार यह नहीं समझती है कि इस तरह से लगातार जो आवाज यहां देश में उठाई जाती है, इससे नैपाल और भारत की मैत्री सुदृढ़ होने में सहायता नहीं मिलती है ?

तस्कर व्यापार क्यों होता है। इस कारण से होता है कि नैपाल में जो यह माल है, उस पर चुंगी कम लगी हुई है। इधर वह कुछ बढ़ी है। इस कारण से चीन का माल, सोवियत संघ का माल, अमरीका, जापान आदि देशों का माल वहां सस्ता पड़ता है, इसलिए वह हमारे यहां स्मगल हो कर आता है। माल आने जाने की जो बात है, इसके सम्बन्ध में क्या सरकार नैपाल सरकार से विचारविमर्श करके इस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करेगी और क्या तस्कर व्यापार जो होता है उस को रोकने के अिए उसके साथ मिल कर सम्मिलित प्रयास करेगी ताकि विलगांव की भावना न पैदा न हो ?

श्री ब० रा० भगत : जी हां, इसीलिये मैंने अभी बताया था कि हम सब को बड़े संयम के साथ और बड़ी हिफ़ाजत के साथ इसके बारे में विचार करना चाहिये।

श्री सीताराम केसरी : जो चीजें नैपाल के द्वारा दूसरे देशों को निर्यात होती हैं, उनके सम्बन्ध में अभी लिमये जी ने प्रश्न किया था। मैं जानना चाहता हूं कि नैपाल से जो चीजें निर्यात होती हैं, क्या आप को हक है कि उनके निर्यात पर आप किसी तरह का प्रतिबन्ध लगायें ? यदि नहीं तो आपका जो माल नैपाल में तस्करी के द्वारा स्मगल किया जाता है, क्या उसी के बारे में विचार करने का तथा उसको रोकने का आपको हक है या नहीं है और क्या उसी की रोकथाम करने के बारे में आप कोई ठोस कदम उठायेंगे या नहीं उठायेंगे ?

श्री ब० रा० भगत : न नैपाल को हक है कि हमारे निर्यात में रुकावट डाले और न हमें हक है कि हम नैपाल के निर्यात में रुकावट डालें। इसीलिए ट्रेड ट्रांजिट ट्रीटी हुई थी और उसमें यह था कि दोनों में व्यापार खुला होगा और आर्थिक व्यवस्था के हित में कोई रोकथाम लगाई जाएगी तो आपस में दोनों सरकारें बात-चीत करके लगायेंगी। जहां तक हमारे यहां से स्मगलिंग का सवाल है, हमारा कर्त्तव्य है कि हम उनको रोकें और इसके लिये हमने कदम उठाये भी हैं।

Decrease in the Export of Iron Ore

*965. SHRI SITARAM KESRI : Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the export of Iron ore has considerably decreased in the last few months ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps taken by Government in regard thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) No, Sir. During calendar year 1968, the exports of iron ore from India in fact increased to about 15.65 million tonnes compared to 13.49 million tonnes in the previous year.

(b) Does not arise.

(c) Strenuous efforts are being made to further increase the exports of iron ore in the coming years.

श्री सीताराम केसरी : नैशनल मिनरल डिवेलेपमेंट कारपोरेशन के चेयरमैन श्री भगवान सिंह ने कहा है कि आयरन ओर के एक्सपोर्ट में हमको भारी घाटा हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि ड्यूटी जो लगाई है दो करोड़ की, उसको कम किया जाये तो घाटा बन्द हो सकता

है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को इसकी खबर है या नहीं है ? सोलह मिलियन टन हम आयरन ओर एक्सपोर्ट करते हैं और इस में से 6 मिलियन टन हम गोआ से भेजते हैं जापान को। अभी अखबारों में यह आया है कि जापान ने रूस के साथ एग्रीमेंट करने का फैसला किया है जिस के तहत वहां से वह आयरन ओर लेगा। इस कारण से जापान को हमारा जो आयरन ओर जाता है उसमें भारी कमी होगी। मैं जानना चाहता हूं कि इस सब की खबर आपको है और अगर है तो इसके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : जी हां, इस बात की हमें खबर है। हम बहुत मुस्तैद हैं। यह सही है कि हमारा एक्सपोर्ट क्वालिटी में तो बढ़ता जाता है लेकिन यूनिट वैल्यू आयरन ओर का कम हो गया है और इस कारण से घाटे की परिस्थिति पैदा हो गई है। साथ ही विदेशी मुद्रा अर्जित करने के रास्ते में एक और बाटल नैक है। यह पोर्टस की है। इससे चार्ज बढ़ते जाते हैं। एक्सपोर्ट ड्यूटी भी है। ये सब परिस्थितियां हमारे सामने हैं और हम इन पर हमेशा विचार करते रहते हैं।

श्री सीता राम केसरी : विगत वर्ष दिल्ली में अंकटाड कान्फ्रेंस हुई थी। उसमें डिवेलेप्ड कंट्रीज को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में तरजीह देने का, इंसेंटिव देने का कमिटमैंट किया था। रूस का हमारे साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार भी है। जापान के साथ हमारा व्यापार है, उसको हमारा एक्सपोर्ट होता है, उसमें जब वह हमारे साथ प्रतियोगिता करता है तो क्या यह चीज उस कमिटमैंट के विपरीत नहीं जाती है और इस कारण से हमारा जो एक्सपोर्ट जापान को होता है आयरन ओर का उसमें कमी नहीं होती है ?

श्री ब० रा० भगत : किसी भी देश को चाहे वह उन्नत हो या अर्द्ध उन्नत हो यह अधिकार हैं कि वह अपने रिसोर्सिस बढ़ाने के उपाय करे। साइबेरिया में आयरन ओर के बहुत रिसोर्सिस हैं। जापान की स्टील इंडस्ट्री हर साल बढ़ रही है। अगर जापान उससे लेता है तो इस में कोई आशंका हमें नहीं होनी चाहिये।

श्री सीता राम केसरी : मेरा प्रश्न दूसरा था। डिवेलेप्ड कंट्रीज ने जो डिवेलेपिंग कंट्रीज हैं उनकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के मामले में मदद करने की बात कही थी, उनको इस मामले में इंसेंटिव देने की बात कही थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस बात में कमी आती है या नहीं आती है ?

श्री ब० रा० भगत : जी नहीं। मैंने यही कहा है कि उनको अपने रिसोर्सिस को एक्सप्लायट करने का अधिकार है।

SHRI D. N. PATODIA : Japan is one of the most important buyers of our iron-ore In this connection, I was surprised to find that firstly Japan purchases a small quantity from India. Secondly, the prices obtained by India for exports to Japan are comparatively very much lower compared to what is paid by Japan to the other countries such as U. S. A., African countries, Chile and Peru. May I know, therefore, the reasons why Indian exports have earned lesser price compared to what other customers get from Japan ? Secondly, may I know what steps Government is proposing to take so that the prices are increased to the level of world market price ?

SHRI B. R. BHAGAT : Japan is still the most important buyer of iron-ore so far as India is concerned and in future also they will continue to be the most important buyer. As regards the reasons for our getting low prices, the main difficulty, apart from the comprable quality of iron-ore, is the shipment. In other areas like Australia or Brazil, their bulk-carriers have the capacity of over 100,000 tonnes whereas our port is

not in a position to take more than 30,000 tonnes. This isthe big bottleneck. We have to take steps to improve the facilities in Vizag and Goa. This will take a few years in the Fourth Plan. We are already behind by ten years. This is one reason. Unless this difficulty is removed, the shipment position cannot improve.

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR : MMTC was formed with a view to eliminating middlemen in the export of minerals and iron-ore. But still we understand that a new class of middlemen are coming up who have to supply different ores to the MMTC. Previously this was directly purchased from the mine-owners. May I know whether there is a shift in the policy ?

SHRI B. R. BHAGAT : A new class of middlemen are coming up ? I do not have that information.

श्री शिंकरे : उप मंत्री महोदय ने अभी अपने वक्तव्य में बताया है कि लोह खनिज का जो निर्यात होता है उसमें घाटा नहीं हुआ है। मैं कहूंगा कि घाटा होता है। गोआ से जो एक्सपोर्ट होता है जापान को तथा दूसरे देशों को उसको आप देखें। मारमागोआ में सोलह फरवरी से स्ट्राइक चल रही है।

डा० मैत्रेयी बसु : यह स्ट्राइक नहीं है, वर्क टू रूल है।

श्री शिंकरे : जो भी हो, उस की वजह से गोवा में बार्जमैन का काम जो 24 घंटे चलता था वह अब 12 घंटे भी नहीं चलता है। वहां का जो लोडिंग अनलोडिंग है उसमें डिफिकल्टी आ गई और इस कारण मार्मागोवा बन्दरगाह की प्रेस्टिज नष्ट हो गई है। इस लिए बहुत से स्टीमर्स जो गोवा आते थे वह गोआ के बन्दरगाह पर न आ कर के दूसरे बन्दरगाहों में जाते हैं जिससे ट्रांसपोर्ट के काम में बहुत डिफिकल्टी आ गई है। तो वहां जो स्ट्राइक हो गया या स्लो डाउन वर्क हो गया जैसा कि डा० मैत्रेयी जी कहती हैं, क्या उस पर आपका ध्यान गया है और गोवा की इस समस्या को हल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं ?

डा० मैत्रेयी बसु : न यह स्ट्राइक है, न स्लो डाउन है।

श्री ब० रा० भगत : 1967 में यह दिक्कत थी और वहां 5 साढ़े 5 मिलियन टन के करीब निर्यात हो सका था। मगर 1968 में बहुत सुधार हुआ है। 7 मिलियन से ज्यादा टन का एक्सपोर्ट हुआ है। हमें उम्मीद है कि और ज्यादा सुधार होगा।

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : The hon. Minister has said that our ports can handle only up to 30,000 tonnes. I would submit that it is not a correct statement. Paradip alone can take in about 60,000 tonnes, if only it is really looked after well. May I know whether it is a fact that an agreement was entered into by the STC for export of 3 million tonnes of iron ore from the Bihar and Orissa mines, and whether it has now been brought down to one million tonnes, and if so, the reason for the same, especially since recently the Paradip Transpart in its resolution has urged upon Government.....

MR. SPEAKER : I wonder the hon. Minister can say now which mine is producing how much. He is only the Minister of Foreign Trade.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : It is a question of the port facilities. I am bringing two points to his notice. An agreement was entered into for 3 million tonnes, and now it has been brought down to one million tonnes. May I know why it has been brought down ? As regards the question whether the export is decreasing, he has said that the export is not decreasing. Secondly, I would like to point out that the port facilities are there at Paradip. Still, may I know why it is being reduced ?

SHRI B. R. BHAGAT : I would like to have notice of the question in regard to why the shipment from Paradip has not picked up.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : May I know why the agreement which was entered into for 3 million tonnes has been brought down to one million tonnes by the STC, if it is not a case of decrease of exports ? Let him give the reasons. I do not know why he should be so rough with Paradip port.

SHRI B. R. BHAGAT : In the case of the Paradip port, the corporation has utilised the facilities available to the maximum extent. As the ore from the Daitari mine was not becoming available, the corporation developed a new unloading site and organised road transport facilities for moving the ore to Paradip. These were some of the difficulties, but they are trying to develop the facilites.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : Please give me a little indulgence. I am not in the habit of disturbing the proccedings of the House.....

MR. SPEAKER : That does not mean that he should disturb now. The hon. Minister has not got the information. There is no use asking him all these questions now.

SHRI S. S. KOTHARI : When development is proceeding a pace a basic change should take place in the pattern of trade. There should be more of export of finished goods and less of export of raw materials. In view of this, may I know at what stage the hon. Minister feels he can put a ban on the export of iron ore and encourage export of more of iron and steel products ? Secondly, may I know whether Government have made an estimate of the reserves ofiron ore in this country so that a stage may not come when there may not be enough of iron ore for our own mills ten or twenty years hence ?

SHRI B. R. BHAGAT : That point is always kept in view. That is why we should not export all our exportable iron ore, but we should conserve it for our own use.

SHRI S. S. KOTHARI : I wanted to know whether he would put a ban at some stage.

SHRI B. R. BHAGAT : No ban at the moment.

SHRI S. S. KOTHARI : He has not replied to my question. Have Government surveyed the iron ore resources in the country and whether there would be enough for our use ?

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : With regard to export of iron ore, the hon. Minister was explaining to the House the harbour difficulties and ship difficulties. I would like to draw the attention of the hon. Minister to the fact that the Japanese when they entered into an agreement with regard to export of iron ore from Bailadilla, also entered into an agreement to give assistance to lay a railway line. It was envisaged that there would be a coordination between the excavation of iron ore and also the development of the shipping facilities and the development of ports. Since Visakhapatnam and Goa happen to be the important ports, what was the action taken all these years to coordinate the efforts regarding promotion of export of iron ore, and whether sufficient amount has been sanctioned to these ports, and if so, whether there has still been a lag in the time-schedule for the exeution of the projects, and the actual difficulties in this regard ?

SHRI B. R. BHAGAT : I entirely agree with the hon. Member that unless there is a coordinated effort at development of the iron ore mines, transporation from the pitheads to the ports and the development of the facilities from the technical point of view, we shall not get the best adventage. It is unfortunate that that has not happened. So far is Visakhapatnam is concerned, already they have decided to take up this question so as to have mechanical loading facilities etc. Thes things are being done, and I hope that it would be completed according to the programme.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : In Visakhapatnam it is awfully behind schedule.

रेशम उद्योग का विकास

* 967 श्री महाराज सिंह भारती : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने